



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 539 राँची, सोमवार,

1 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 जून, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-40/2015 का.- 4917-- श्री सतीश कुमार झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला, सम्प्रति- सेवा से मुक्त के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-10(ii)/स्था०, दिनांक 04.01.2016 द्वारा प्रपत्र-क में गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-क में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1 ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 28.09.2014 से 14.07.2015 तक इनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुये पालकोट प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम कोयनजाली, पंचायत-बंगरू अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत जामुनीजाम से लिटीया बगीचा तक 1.5 (डेढ़) किलो मीटर मोरम पथ निर्माण कार्य में मास्टर रॉल पास करने के एवज में 10,000/- (दस हजार रुपये) घूस लेते हुये निगरानी ब्यूरो, राँची के टीम के द्वारा रंगे होथों पकड़े गये। जिसका निगरानी थाना काण्ड संख्या-36/15 दिनांक 14.07.2015 है।

आरोप सं०-2. श्री सतीश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के उक्त कृत्य से सरकारी नियम का उल्लंघन कर प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत लेने के कारण सरकारी राशि की काफी क्षति के साथ-साथ सरकार की छवि धूमिल हुई।

आरोप सं०-3. श्री सतीश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के द्वारा उक्त कृत कार्य सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(i) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के प्रसंग में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8023, दिनांक 16.09.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०,

विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-85, दिनांक 02.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-6285, दिनांक 17.05.2017 श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-8387, दिनांक 26.07.2017 द्वारा स्मारित किया गया, पुनः विभागीय पत्रांक-11519, दिनांक 20.11.2017 द्वारा स्मारित करते हुए यह अंकित किया गया आपको जो भी कागजात की आवश्यकता है दिनांक 22.11.2017 तक विभाग में उपस्थिति होकर संबंधित संचिका का अवलोकन कर प्राप्त करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा का एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।

श्री कुमार को अंतिम अवसर देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः 7 दिनों के भीतर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अंतिम रूप से समर्पित करने का अनुरोध किया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि उत्तर अप्राप्त रहने पर यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा विभाग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-416, दिनांक 15.01.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री कुमार को सेवा से मुक्त किये जाने के संबंध में सहमति की माँग की गयी।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-516, दिनांक 22.02.2018 द्वारा श्री कुमार को सेवा से मुक्त करने संबंधी दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है।

तत्पश्चात् दिनांक 13.03.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री कुमार को सेवा से मुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसके उपरान्त विभागीय संकल्प सं0-222(HRMS) दिनांक 15.03.2018 द्वारा श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से मुक्त किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका W.P.(S) No.-2312/18 दायर की गई तथा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष दिनांक 10.04.2018 को पुनर्विचार अभ्यावेदन दाखिल किया गया। श्री कुमार के पिता द्वारा इस संबंध में पुनर्विचार अपील न्याय करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध किया गया, श्री कुमार द्वारा पुनः दिनांक 22.01.2019 को मुख्य सचिव, झारखण्ड के समक्ष एक अन्य पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। पुनः श्री कुमार द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.05.2019 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 04.04.2019 को रिट याचिका W.P.(S) No.-2312/18 में पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराया गया।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 04.04.2019 को रिट याचिका W.P.(S) No.-2312/18 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। अपने अपील अभ्यावेदन में श्री कुमार द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के लम्बित रहने के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ न हो सकने का तर्क दिया गया है, जो अमान्य प्रतीत होता है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-8000 दि० 02.09.2015 के आलोक में आपराधिक वादों के लम्बित होने की स्थिति में भी सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के द्वारा परिवादकर्त्ता श्री मुकुट एकका से रिश्वत के रूप में 10,000/- ₹० लिये जाने; योजनाओं के कार्यान्वयन में रिश्वत लेने से सरकार की छवि धुमिल होने एवं सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-3(1)(i) के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित एक अन्य पुनर्विचार अभ्यावेदन में संवर्ग के अन्य पदाधिकारियों पर सदृश्य मामले में विभागीय कार्यवाही आरंभ कर उन विभागीय कार्यवाहियों को माननीय न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित रहने के आधार पर स्थगित करने का तथ्य अंकित किया गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि श्री कुमार के विरुद्ध आपराधिक मामला उनके झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में दिनांक 19.08.2013 को योगदान देने के पश्चात् परीक्ष्यमान अवधि में दर्ज किया गया है। श्री कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में अंकित पदाधिकारियों में श्री शिवाजी भगत को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक वाद परीक्ष्यमान अवधि के बाद प्रारंभ हुए हैं। श्री शिवाजी भगत के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया है, जबकि श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके विरुद्ध गठित सभी आरोपों को संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री कुमार की झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं०-7275 दि० 10.08.2013 की कंडिका-‘ख’ में स्पष्ट किया गया है कि परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सतीश कुमार, झा०प्र०से०, (द्वितीय सीमित बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला, सम्प्रति-सेवा से मुक्त द्वारा समर्पित पुनर्विचार/अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के अंतर्गत सेवा से मुक्त करने के निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
